



## ब्रेकिजट समस्याग्रस्त क्यों हैं?

यह आलेख सापान्च अध्ययन प्रश्न-पत्र-॥  
( अंतर्राष्ट्रीय संबंध ) से संबंधित है।

### इंडियन एक्सप्रेस

17 दिसंबर, 2018

23 जून, 2016 को एक जनमत संग्रह में, ब्रिटिश नागरिकों ने ईयू छोड़ने के पक्ष में कम मतदान किया, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ अंतर केवल 4% का ही था, अर्थात् 52% से 48% तक।

पिछले हफ्ते विकास की श्रृंखला में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने यूरोपीय संघ के साथ अपने ब्रेकिजट सौदे पर एक संसद वोट को टाल दिया और अपने स्वयं के कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के अविश्वास से बच गयीं, जिसके बाद यूरोपीय संघ के नेताओं ने सौदे पर पुनः बातचीत करने से इंकार कर दिया। इस आलेख में हम जानेंगे कि ब्रिटेन के प्रस्तावित निकास के रास्ते में क्या-क्या बाधाएं हैं?

#### क्यों बाहर निकलें और कब?

23 जून, 2016 को एक जनमत संग्रह में, ब्रिटिश नागरिकों ने ईयू छोड़ने के पक्ष में कम मतदान किया, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ अंतर केवल 4% का ही था, अर्थात् 52% से 48% तक। ब्रिटेन 29 मार्च 2019 को यूरोपीय संघ से बाहर निकल रहा है। विभिन्न पहलुओं में, यूके और यूरोपीय संघ को व्यापार सौदा करने और व्यवसाय को समायोजित करने का समय देने के लिए एक संक्रमण अवधि पर सहमति हुई है। इसका मतलब है कि यदि वापसी समझौते को मजूरी मिल जाती है, तो 29 मार्च, 2019 के बाहर निकलने और 31 दिसंबर, 2020 के बीच कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, बीबीसी के एक लेख के अनुसार।

इस समझौते में कई मुद्दों को शामिल किया गया है, जैसे कि यूके को साझेदारी तोड़ने के लिए यूरोपीय संघ को कितना भुगतान करना होगा (लगभग 39 बिलियन यूरो, बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार) और ईयू में रहने वाले यूके नागरिकों के साथ-साथ ब्रिटेन में रहने वाले ईयू नागरिकों के साथ क्या होगा। इस सौदे में एक मुद्दा, जो विशेष रूप से विवादास्पद साबित हुआ है, वह है उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के बीच की भौतिक सीमा, जब यह ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच सीमा बन जाएगी। आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड

उत्तरी आयरलैंड यूके का हिस्सा है, जबकि आयरलैंड गणराज्य ब्रेकिजट के बाद ईयू का हिस्सा बनगा। ईयू व्यवस्था के तहत, वर्तमान में आयरलैंड गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड के बीच लोगों और वस्तुओं के लिए सीमा पार करना आसान है, लेकिन अब डर है कि ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद यह नहीं रहेगा। बहुत से लोगों के मन में यह भी डर है कि उत्तर और दक्षिण के बीच की बाधाएं 1998 में समाप्त हुए 30 साल के संघर्ष के दौरान प्रचलित तनाव को पुनर्जीवित कर सकती हैं।

हालाँकि, इसका समाधान करने के लिए, वापसी समझौते में बैकस्टॉप योजना शामिल है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सीमा तब तक सबके लिए इसी तरह आसान बनी रहेगी, जब तक ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच एक व्यापार समझौता समाप्त नहीं हो जाता है। दूसरी तरफ, विरोधियों का मानना है कि बैकस्टॉप योजना यूके को ब्रेकिजट के बाद भी ईयू विनियमन के अधीन छोड़ देगी।

गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ब्रेकिजट ब्रिटेन का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक निर्णय रहा है। कहा जा रहा है कि अगर यह व्यवस्था लागू हो गई तो यह ब्रिटेन की 2.8 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को आकार देगी। राज्य की एकता के लिए इसके दूरगामी परिणाम होंगे और यह निर्धारित करेगा कि क्या लंदन शीर्ष दो वैश्विक वित्तीय केंद्रों में से एक के रूप में अपनी जगह बचा पाएगा या नहीं।

#### आगे की राह

यूके पहले से ही समझौते के साथ फंसा हुआ प्रतीत होता है। यदि मे संसद से पहले इसे पाने में विफल रहती हैं (जहाँ इन्हें ऐसा करने में तीन सप्ताह लगेंगे), तो यह कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। बीबीसी लेख ने कई संभावित परिदृश्यों को शामिल किया है, जिसमें बिना किसी समझौते के यूरोपीय संघ को छोड़ देना, एक अन्य जनमत संग्रह (इसे नए कानून और संसद में बहुमत समर्थन की आवश्यकता होगी) और एक आम चुनाव, शामिल है।

हालाँकि, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्रियों का कहना है कि सरकार दूसरे जनमत संग्रह की तैयारी नहीं कर रही है, सरकार समझौते में कुछ बदलाव करके उसे पास करने पर विचार कर रही है।

ब्रिटिश प्रकाशन द वीक में एक लेख के मुताबिक, आलोचकों का तर्क है कि बिना किसी सौदे का छोड़ना व्यवसायों के लिए विनाशकारी साबित होगा, सीमाओं पर अराजकता का निर्माण होगा, खाद्य कीमतों में वृद्धि होगी और आवश्यक वस्तुओं की कमी होगी।



## ब्रेकिंजट

### क्या है?

- यह मुख्यतः दो शब्दों ब्रिटेन (Britain) और एग्जिट (Exit) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ब्रिटेन का यूरोपीय संघ (European Union-EU) से बाहर निकलना है।
- ब्रिटेन की जनता ने ब्रिटेन की पहचान, आजादी और संस्कृति को बनाए रखने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ से बाहर जाने का फैसला लिया।
- यूरोपीय संघ (निकासी) विधेयक के कानून बन जाने के उपरांत इसने 2017 के यूरोपीय समुदाय अधिनियम का स्थान ले लिया है।
- 29 मार्च, 2019 तक ब्रिटेन को यूरोपीय संघ छोड़ देना है। ब्रेकिंजट डे यानी 29 मार्च, 2019 से ब्रिटिश कानून ही मान्य होंगे।
- 29 मार्च, 2019 से 21 महीने का संक्रमण चरण (Transition phase) शुरू होगा और यह दिसंबर 2020 के अंतिम दिन खत्म होगा।
- यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के समझौते के लिये तैयार मसौदे को ब्रेकिंजट ड्राफ्ट डील कहा जा रहा है।

### बाहर निकलने की मांग क्यों?

#### 1. सदस्यता शुल्क

- ईयू हर साल सदस्यता शुल्क के तौर पर ब्रिटेन से बिलियन ऑफ पाउंड लेता है तथा बदले में उसे बहुत कम राशि मिलती है।
- यह राशि लगभग 13 बिलियन पाउंड है, जो दूसरे देशों की अपेक्षा काफी अधिक है।
- सदस्यता के लिये ईयू के सभी 28 देश कुछ-न-कुछ राशि EU को देते हैं, लेकिन ब्रिटेन के लिये यह राशि काफी अधिक है और बदले में उसे सिर्फ 7 बिलियन यूरो वापिस मिलते हैं। अतः UK (ब्रिटेन) को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

#### 2. प्रशासनिक अड़चन

- UK में कोई भी प्रशासनिक कार्य करने के दौरान काफी अड़चनें आती हैं। बहुत अधिक डॉक्यूमेंटेशन तथा बहुत सारे कार्यालयों द्वारा काम होता है। कई सारी प्रणालियाँ हैं, जिनको पूरा करना पड़ता है।
- तमाम ऐसे प्रतिबंध हैं, जिनसे UK के विकास में रुकावट आ रही है तथा यूरोपीय यूनियन UK को पीछे ढकेल रही है, उसे आगे बढ़ने से रोक रही है।

#### 3. स्वायत्तता

- लोगों का कहना है कि ईयू इंलैंड को उसके अधिकारों और स्वयं कानून बनाने से वर्चित कर रहा है। खासतौर से फिशरीज से संबंधित कानून।
- UK के चारों ओर फिशरीज इंडस्ट्री काफी विकसित है और इस उद्योग को लेकर नियम-विनियम ईयू के द्वारा बनाए जाते हैं।
- ईयू की संसद तय करती है कि UK के मछुआरे कितनी मात्रा में मछली पकड़ सकते हैं तथा एक्सपोर्ट रेट क्या रहेगा।

#### 4. अर्थव्यवस्था

- अगर यूरोपीय यूनियन से UK अलग हो जाता है, तो वह अपने

आपको फाइनेंसियल सुपर पॉवर बना सकता है क्योंकि लंदन को पहले से ही वित्तीय राजधानी कहा जाता है। वहाँ का वित्तीय बाजार दुनिया के बड़े बाजारों में से एक है।

#### 5. इमीग्रेशन

- यह एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि सीरिया में सिविल वार के चलते काफी संख्या में अप्रवासी भागकर यूरोप आ रहे हैं।
- इमीग्रेशन नीति भी ईयू तय करता है, न कि UK, अगर वह ईयू से हट जाता है तो उसे अपनी खुद की इमीग्रेशन नीति तय करने का अधिकार होगा।

### बाहर निकलने की प्रक्रिया?

- ईयू से बाहर निकलने की प्रक्रिया लिस्बन ट्रीटी (Lisbon Treaty) के आर्टिकल 50 में दी गई है। इस आर्टिकल को लागू करना होगा। अगर एक बार आर्टिकल 50 लागू हो जाए तो फिर उसे वापस तभी लिया जा सकता है जब सभी सदस्य देश इसके लिये सहमत हों।
- सदस्यता छोड़ने की शर्तें पर 27 सदस्य देशों की संसदों की सहमति लेनी जरूरी है जो एक लंबी प्रक्रिया है।
- लिस्बन ट्रीटी ईयू को स्थापित करने वाली कुछ प्रमुख संधियों में से एक है। यह 2009 में लागू की गई थी।
- ईयू से बाहर निकलने के लिये दो साल का नोटिस पीरियड दिया जाना जरूरी होता है और यह उस दिन से शुरू माना जाएगा जब UK की संसद बाहर निकलने के फैसले को स्वीकृत कर देगी।
- बाहर जाने के बाद अगर कोई देश दोबारा ईयू में शामिल होना चाहता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। दोबारा शामिल होने जैसे प्रस्तावों पर आर्टिकल 49 के तहत विचार किया जाएगा।

### भारत पर प्रभाव

- सिर्फ ब्रिटेन में 800 भारतीय कंपनियाँ हैं। जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। भारतीय आईटी कंपनियों की 6 से 18 प्रतिशत कमाई ब्रिटेन से होती है।
- भारत में कुल एफडीआई का 8 प्रतिशत हिस्सा UK से आता है। इसका असर भारत के कारोबार पर कम पड़ेगा लेकिन ब्रिटेन के साथ अलग से व्यापारिक समझौते करने पड़ेंगे।
- भारतीय कंपनियों की ब्रिटेन में रुचि की एक बड़ी वजह यह है कि ब्रिटेन के रास्ते भारतीय कंपनियों की यूरोप के 28 देशों के बाजार तक सीधी पहुँच हो जाती है।
- यूरोप के देशों से भारत को नए करार करने होंगे। इससे कंपनियों के खर्च में इजाफा होगा। साथ ही हर देश के नियम-कानूनों का भी पालन करना होगा।
- ब्रेकिंजट के बाद जिन भारतीय कंपनियों ने ब्रिटेन में पैसा लगाया है उनकी बैलेंसशीट पर सीधा असर पड़ेगा।
- ब्रिटेन पर दाँव लगाने वाली कुछ बड़ी भारतीय कंपनियाँ हैं-टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, वॉकहार्ट, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, इप्का लैब और कमिंस।

संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

1. हाल ही में चर्चा में रहे ब्रिटेन के 'ब्रेकिट निर्णय' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
  1. यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया से सम्बंधित लिस्बन ट्रीटी का आर्टिकल-50 यदि एक बार लागू हो गया, तो इसे वापस तभी लिया जा सकता है जब सभी सदस्य देश इसके लिए सहमत हो।
  2. यूरोपीय संघ के सभी सदस्य नाटो (NATO) के भी सदस्य हैं।  
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
    - (a) केवल 1
    - (b) केवल 2
    - (c) 1 और 2 दोनों
    - (d) न तो 1, न ही 2

प्रश्न: 'द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से ब्रेकिट ब्रिटेन का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक निर्णय रहा है।' इस निर्णय के संभावित सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करते हुए भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को भी स्पष्ट कीजिए तथा इस संदर्भ में अपने सुझावों को भी बताइए। ( 250 शब्द )

नोट : 15 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।

